

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 नवम्बर, 2015

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तराखण्ड के पत्रांक- 356(i)/सूडा/एस0जेएस0आर0वाई0/2015-16, दिनांक 10.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)" हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या: G-24011/4/2015-UPA FTS:13207, दिनांक 30.06.2015 (02 पत्र) द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹2,26,02,000/- एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹75,34,000/-, इस प्रकार कुल ₹3,01,36,000/- (रुपये तीन करोड़ एक लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) योजना का क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा शहरी विकास निदेशालय (SLNA) के सतत अनुश्रवण में किया जायेगा।
- (ii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- (iii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (iv) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) उक्त अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा तक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
- (vi) योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (vii) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- (viii) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रपत्र/आर0एफ0पी0 आमंत्रित किए जाते समय प्रपत्र/अभिलेख के अन्तर्गत, योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात 02 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का प्रतिबन्ध रखा जायेगा।
- (ix) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निकायों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा ताकि एक कार्य हेतु दो निधि से धनराशि अवमुक्त न हो।
- (x) योजनाओं के सापेक्ष पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करते हुए योजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा, जिससे Cost Overrun and time over run की स्थिति से बचा जा सके और स-समय उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किए जा सकें।
- (xi) शहरी विकास निदेशालय द्वारा नगर निकाय/कार्यदायी संस्था से योजनाओं का अद्यतन प्रगति विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (xii) योजनान्तर्गत निर्धारित O&M Cost एवं Other Charges (डी0पी0आर0 गठन एवं अन्य व्यय) हेतु निर्धारित धनराशि शहरी विकास निदेशालय स्तर पर ही रखी जाय एवं आवश्यकतानुसार निदेशालय स्तर पर व्यय की जाय या स्थानीय निकायों को अवमुक्त की जाय।
- (xiii) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xiv) धनराशि का दिनांक 31-03-2016 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय के नामे ₹2,38,07,440/-, अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-08-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय के नामे ₹54,24,480/- तथा अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-08-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42- अन्य व्यय के नामे ₹9,04,080/-डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 758/XXVII(2)/2015, दिनांक 09.11.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- एलॉटमेंट आई0डी0 सं0-S.15/1130203, S.15/11300204 एवं S.15/11310205

भवदीय,

(डी0एस0 गब्याल)
सचिव।

संख्या-1501 (1)/IV(2)-श0वि0-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी।
8. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-1 एवं 2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

